CEDSI TIMES

Your Skilling Partner...

लद्दाख के डेयरी विकास को गति मिली: एलजी मिश्रा ने एग्लिंग में मिल्क पाश्चराइजेशन प्लांट का उद्घाटन किया

डेयरी बुनियादी ढांचे को बढ़ाने और स्थानीय डेयरी किसानों की सहायता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, लद्दाख के उपराज्यपाल (एलजी) डॉ. बीडी मिश्रा (सेवानिवृत्त) ने एग्लिंग में एक अत्याधुनिक मिल्क पाश्चराइजेशन प्लांट का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, डॉ. मीनेश शाह की उपस्थिति देखी गई, जिन्होंने एलजी मिश्रा को भारतीय सेना की आवश्यक दूध आवश्यकताओं को संबोधित करते हुए प्रति घंटे 2,000 लीटर दूध को पास्चुरीकृत करने की संयंत्र की क्षमता के बारे में बताया। लद्दाख में तैनात.

4.62 करोड़ रुपये के निवेश के साथ, यह संयंत्र क्षेत्र की डेयरी मांगों, विशेष रूप से भारतीय सेना के लिए दैनिक आधार पर 50,000 लीटर दूध की आवश्यकता को पूरा करने में महत्वपूर्ण योगदान देगा। इस पहल से स्थानीय डेयरी किसानों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होने और आय बढ़ने की उम्मीद है। बैठक के दौरान कारगिल में इसी तरह के संयंत्रों की योजना और रणनीतिक दूध वितरण योजनाओं पर भी चर्चा की गई। उपराज्यपाल ने उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादन को सुनिश्चित करने के लिए शीतकालीन बुनियादी ढांचे को उन्नत करने और दूध के नमूनों का कठोर परीक्षण करने की आवश्यकता पर जोर दिया।

उत्तर प्रदेश ने पशुधन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए आवारा मवेशी अभियान और डेयरी पहल शुरू की

उत्तर प्रदेश के पशुपालन मंत्री धर्मपाल सिंह ने 1 नवंबर से 31 दिसंबर तक एक विशेष अभियान की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य राज्य में सभी आवारा मवेशियों को नामित गौशालाओं में स्थानांतरित करना है। इस पहल का उद्देश्य आवारा मवेशियों की समस्या को कम करना और उनका कल्याण सुनिश्चित करना है। इसके अतिरिक्त, मवेशियों के लिए कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा, अंततः नस्लों को बढ़ाने और दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए लखनऊ में एक अत्याधुनिक प्रयोगशाला स्थापित की जा रही है।

नस्ल सुधार और दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए, राष्ट्रीय गोकुल मिशन 200 गायों के लिए 4 करोड़ रुपये की लागत से नस्ल गुणन फार्मों की स्थापना शुरू कर रहा है। नंदबाबा दूध मिशन एक साथ गति में है, दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए कई जिलों में 25 देशी गायों की 35 डेयरियां स्थापित की जा रही हैं। देशी गाय की किस्मों की खरीद के लिए किसानों को सब्सिडी प्रदान की जा रही है, उनके बीमा और उत्तर प्रदेश में परिवहन पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है।

अरुणाचल प्रदेश सहकारी ढांचे के भीतर डेयरी क्षेत्र के विकास में अग्रणी है

मुख्य सचिव धर्मेंद्र की अध्यक्षता में अपनी उद्घाटन बैठक में, समिति ने 500 मीट्रिक टन अनाज भंडारण सुविधा के लिए नामसाई लैंप्स द्वारा एक पायलट परियोजना का समर्थन किया। सत्र में केंद्रीय सहयोग मंत्रालय द्वारा विभिन्न योजनाओं और पहलों को लागू करने में राज्य के सहकारी विभाग की प्रगति की व्यापक समीक्षा भी की गई, जिसमें प्रभावी परिणामों के लिए विभागों में राज्य योजना योजनाओं में अभिसरण की आवश्यकता पर जोर दिया गया।

अरुणाचल प्रदेश राज्य सहकारी विकास समिति (एससीडीसी) ने 490 से अधिक सहकारी समितियों की स्थापना को मंजूरी देकर, डेयरी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना शुरू की है। इस अभूतपूर्व कदम में अगले पांच वर्षों में राज्य भर में फैली 150 बड़ी बहुउद्देशीय सहकारी समितियों (LAMPS), 157 डेयरी सहकारी समितियों और 184 मत्स्य पालन सहकारी समितियों का निर्माण शामिल है।

पशुपालन और डेयरी विभाग ने झारखंड में 'ए-हेल्प' कार्यक्रम शुरू किया

भारत सरकार के पशुपालन और डेयरी विभाग ने राज्य के पशुधन क्षेत्र में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को पहचानते हुए, झारखंड में 'ए-हेल्प' (पशुधन उत्पादन के स्वास्थ्य और विस्तार के लिए मान्यता प्राप्त एजेंट) कार्यक्रम की शुरुआत की। मंत्री श्री बादल पत्रलेख ने कार्यक्रम की अभूतपूर्व प्रकृति पर प्रकाश डाला, जो महिलाओं को रोग नियंत्रण, पशु टैगिंग और पशुधन बीमा में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए मान्यता प्राप्त एजेंटों के रूप में सशक्त बनाता है।

ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली पशु सखियों को स्थानीय पशुओं को पशु चिकित्सा देखभाल, प्रजनन सहायता और दवा प्रदान करने के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। उनका चयन उनकी बुनियादी साक्षरता और संचार कौशल के आधार पर किया जाता है, उनकी सेवाओं के लिए पशुधन मालिकों से मामूली शुल्क लिया जाता है।

श्रीमती पशुपालन एवं डेयरी विभाग की सचिव अलका उपाध्याय ने पशुधन क्षेत्र के व्यापक विकास में पशुधन और महिलाओं की आवश्यक भूमिकाओं पर जोर दिया। उन्होंने बढ़ते पशुधन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार की सराहना की और पशुधन उत्पादन के स्वास्थ्य और विस्तार के लिए मान्यता प्राप्त एजेंटों (ए-हेल्प) की अवधारणा पेश की, जिसका उद्देश्य पशु चिकित्सा संस्थानों और पशुधन मालिकों के बीच अंतर को पाटना है।
कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सक्रिय ए-हेल्प पहल, ग्रामीण मंत्रालय के तहत पशुपालन और डेयरी विभाग (डीएएचडी) और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) के बीच एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) का परिणाम है। विकास (एमओआरडी), भारत सरकार।

लॉन्च इवेंट के दौरान, पशु सखियों को ए-हेल्प किट वितरित किए गए, जो पशुधन क्षेत्र में महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में एक ठोस कदम है। इस कार्यक्रम में प्रगतिशील किसानों और पशु सखियों सहित पर्याप्त भागीदारी हुई।

डीबीटी-एनआईएबी वैज्ञानिकों ने स्वदेशी मवेशी जीनोम डिकोडिंग में सफलता हासिल की है

प्रमुख वैज्ञानिक, एनआईएबी के निदेशक जी. तारू शर्मा ने भविष्य के अनुसंधान के लिए इस जीनोम डिकोडिंग के महत्वपूर्ण निहितार्थों पर प्रकाश डाला। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यह सफलता न केवल मवेशियों की नस्लों के बारे में हमारी समझ को गहरा करेगी बल्कि

अत्यधिक उत्पादक और लचीले स्वदेशी मवेशियों के विकास में भी योगदान देगी। निकट भविष्य में स्वदेशी मवेशियों को विदेशी नस्लों और क्रॉसब्रेड किस्मों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम बनाने के लिए ऐसी प्रगति महत्वपूर्ण है।

स्वदेशी मवेशी विभिन्न बीमारियों और सूखे और गर्मी जैसी प्रतिकूल पर्यावरणीय परिस्थितियों के प्रति अपने अंतर्निहित लचीलेपन के लिए जाने जाते हैं। अपने पश्चिमी या विदेशी समकक्षों की तुलना में उनके पास विशिष्ट गुण होते हैं। नव निर्मित संदर्भ जीनोम से इन अद्वितीय लक्षणों के लिए जिम्मेदार जीन और विविधताओं में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करने, सटीक पहचान और संरक्षण प्रयासों को सक्षम करने की उम्मीद है।

नवीन 'ट्रायो-बिनिंग दृष्टिकोण' का उपयोग करते हुए, वैज्ञानिकों ने उल्लेखनीय सटीकता के साथ 'साहिवाल' और 'थारपारकर' के जीनोम को सावधानीपूर्वक इकट्ठा किया। यह माता-पिता द्वारा लंबी और छोटी पढ़ी जाने वाली अनुक्रमण तकनीकों को नियोजित करके अनुक्रमित करके हासिल किया गया था। इस प्रक्रिया में हासिल की गई सटीकता एनआईएबी के शोधकर्ताओं के समर्पण और दृढ़ता का प्रमाण थी।

मवेशियों की देशी नस्ल. यूएसडीए-एआरएस (यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर-एग्रीकल्चर रिसर्च सर्विस) के सहयोग से हासिल की गई यह उपलब्धि, स्वदेशी मवेशियों की अनूठी विशेषताओं को समझने और बढ़ाने की अपार संभावनाएं रखती है।

डेयरी में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए श्रीलंका अमूल की मदद लेगा

श्रीलंका भारत के प्रसिद्ध अमूल डेयरी विकास मॉडल से लाभान्वित होने के लिए तैयार है, जिसका लक्ष्य अपने डेयरी उद्योग को बढ़ावा देना और आत्मनिर्भरता हासिल करना है। डेयरी क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को लक्ष्य करते हुए भारत के राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी), गुजरात सहकारी दूध विपणन महासंघ (जीसीएमएमएफ) और श्रीलंका के कारगिल्स के बीच एक संयुक्त उद्यम समझौता स्थापित किया गया है। एनडीडीबी और जीसीएमएमएफ के पास बहुमत हिस्सेदारी होगी, जबकि कारगिल्स के पास शेष हिस्सेदारी होगी। सरकार द्वारा नियंत्रित कुछ मिल्को डेयरी फार्म और ब्रांड हाईलैंड इस संयुक्त उद्यम के अंतर्गत आएंगे।

वर्तमान में, श्रीलंका अपनी घरेलू डेयरी मांग का लगभग 40% पूरा करता है, शेष के लिए आयात पर निर्भर करता है। जीसीएमएमएफ के प्रबंध निदेशक जयेन मेहता के अनुसार, नवगठित संयुक्त उद्यम का लक्ष्य एक दशक के भीतर श्रीलंका को डेयरी उद्योग में आत्मनिर्भर बनाना है। उद्यम में निवेश संयुक्त उद्यम को हस्तांतरित परिसंपत्तियों के मूल्यांकन के आधार पर निर्धारित किया जाएगा।

समझौते पर श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और श्रीलंका में भारत के उच्चायुक्त गोपाल बागले की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए। यह सहयोग अमूल के सफल सहकारी डेयरी मॉडल का उपयोग करके श्रीलंका के डेयरी उद्योग को ऊपर उठाने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जिसे विश्व स्तर पर दोहराया गया है। यह श्रीलंका के डेयरी उत्पादन को बढ़ाने और आयात पर निर्भरता को कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे देश में अधिक आत्मनिर्भर और मजबूत डेयरी क्षेत्र का मार्ग प्रशस्त होगा।

ओडिशा का लक्ष्य दुग्ध आत्मनिर्भरता है: प्रधान सलाहकार त्रिपाठी

एक महत्वपूर्ण घोषणा में, मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार असित त्रिपाठी ने घोषणा की कि ओडिशा पशुपालन, दूध, मांस और अंडा उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए तैयार है। त्रिपाठी ने इस बात पर जोर दिया कि राज्य में किसानों को "मुख्यमंत्री कृषि उद्योग योजना" के माध्यम से सफल उद्यमियों में बदलने के लिए विभिन्न सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।

एपीआईसीओएल, मत्स्य पालन और पशु संसाधन विकास विभाग और कृषि विभाग के सहयोग से किए गए एक हालिया सर्वेक्षण में कई खेती में लगे 6,000 कृषक परिवारों की पहचान की गई। त्रिपाठी ने सर्वेक्षण में पहचाने गए कुशल किसानों को प्रोत्साहन प्रदान करने के साथ संभावित किसानों को समृद्ध उद्यमियों में विकसित करने के उद्देश्य से एक योजना तैयार करने की योजना की घोषणा की।

मत्स्य पालन और पशु संसाधन विकास विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान, त्रिपाठी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि ओडिशा में लगभग 60 लाख परिवार कृषि और संबंधित गतिविधियों में लगे हुए हैं, जो उनके लिए उद्यमिता में उद्यम करने के लिए अनुकूल माहौल प्रस्तुत करता है। उन्होंने सफल उद्यमी बनने के लिए इन किसान परिवारों को समर्थन और बढ़ावा देने की आवश्यकता पर जोर दिया।

पशुपालन को बढ़ाने के लिए, ओडिशा क्रॉस-ब्रीड गायों का समर्थन कर रहा है, चारा वितरित कर रहा है और पशुपालन में सब्सिडी प्रदान कर रहा है। उत्पादकों और बाज़ारों के बीच संपर्क बढ़ाने के प्रयास चल रहे हैं। इसके अलावा, राज्य ने आत्मनिर्भरता के व्यापक लक्ष्य के अनुरूप, वाणिज्यिक पोल्ट्री फार्मों, अर्ध-व्यावसायिक पोल्ट्री फार्मों और पिछवाड़े पोल्ट्री के माध्यम से अंडे और मांस उत्पादन में वृद्धि देखी है।

बैठक में मत्स्य पालन एवं पशु संसाधन विकास विभाग के प्रधान सचिव सुरेश कुमार वशिष्ठ और ओएमएफईडी और एपीआईसीओएल के सदस्यों सहित प्रमुख अधिकारियों ने भाग लिया।

सीईडीएसआई और टाटा ट्रस्ट ने बेहतर पशु प्रबंधन के उद्देश्य से डेयरी फार्मिंग को बढ़ाने के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम पर सहयोग किया

सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर डेयरी स्किल्स इन इंडिया (सीईडीएसआई) ने टाटा ट्रस्ट द्वारा वित्त पोषित पहल "सेंटर फॉर माइक्रोफाइनेंस" से जुड़े प्रगतिशील किसानों और विस्तार कार्यकर्ताओं के लिए एक क्षमता निर्माण कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम का एजेंडा बेहतर पशु प्रबंधन तकनीकों पर ज्ञान का प्रसार करना है। कार्यक्रम केवीके, उदयपुर में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें 25 उम्मीदवारों की उत्साहपूर्ण भागीदारी देखी जा रही है। प्रशिक्षण कार्यक्रम में बेहतर पशु प्रबंधन से संबंधित कई महत्वपूर्ण पहलुओं को शामिल किया गया, जिसमें इष्टतम पोषण, स्वास्थ्य निगरानी, प्रजनन रणनीतियों और कुशल कृषि संचालन जैसे विषय शामिल थे। इन उन्नत तकनीकों को एकीकृत करके, डेयरी किसान अपने पशुधन की भलाई और उत्पादकता में उल्लेखनीय वृद्धि कर सकते हैं

हम कौन हैं?

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के तहत भारतीय कृषि कौशल परिषद (ASCI) के तत्वावधान में काम करने वाली एक स्वायत्त संस्था "सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस फॉर डेरी स्किल्स इन इंडिया (CEDSI)", किसानों की आजीविका के सशक्तिकरण और बेहतरी में मदद करने के लिए, वेतनभोगी कर्मचारी, और डेयरी मूल्य श्रृंखला में अन्य हितधारक।

सीईडीएसआई सदस्यता उद्योग के नेताओं, नीति निर्माताओं, विकास चिकित्सकों, डेयरी वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं, छात्रों और किसानों को डेयरी उद्योग के लिए आसन्न महत्व के मुद्दों पर बहस और चर्चा करने के लिए एक अनूठा मंच प्रदान करेगी।

Centre of Excellence for Dairy Skills in India

Join Our Membership Drive and Get Benefits of

- Platform to interact with other members in the sector
- Recognize your organization with CEDSI Yearly Awards and Recognition
- Networking opportunities with corporate leaders and government authorities
- Chance to reach across the board through advertising in our press releases, news and articles
- Special costs of training in Skill India Certified Programmes
- Consultative and advisory services to help members
- Access to our Journal and Publications
- Consulting and advisory services to help members
- Expert advice in day-to-day operations and management of livestock /farm productions
- Periodic e-newsletter for the latest news, govt. announcement and schemes in dairy sectors
- Free registration on the job portal and regular updates on job vacancies in the sector
- Updates on training programs of CEDSI and access to the training calendar

Who Can Become a Member -

www.cedsi.in @cedsi_india

CEDSI : रविविंग स्किल्स एंड जनरेटिंग लाइवलीहुड

किसानों/छात्रों/उद्यमियों के लिए कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम

- डेयरी किसान / उद्यमी
- डेयरी फार्म पर्यवेक्षक
- डेयरी कार्यकर्ता
- पशु स्वास्थ्य कार्यकर्ता
- कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन
- पशु चिकित्सा क्षेत्र सहायक
- पशु चिकित्सा नैदानिक सहायक
- बछड़ा पालन
- कृषि उपकरण तकनीशियन
- डेयरी फार्म अर्थशास्त्र और प्रबंधन
- उद्योग संरेखित प्रमाणन कार्यक्रम (बेरोजगार युवा और छात्र)

एफपीओ उन्मुख प्रशिक्षण कार्यक्रम

- उत्पाद प्रौद्योगिकी और प्रक्रियाओं पर एफपीओ सदस्य अभिविन्यास।
- एफपीओ मार्केट लिंकेज
- एफपीओ शासन
- एफपीओ लेखा

डेयरी कॉरपोरेट्स और सहकारी समितियों के लिए प्रमुख कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम

- चिलिंग प्लांट तकनीशियन
- बल्क मिल्क कूलर ऑपरेटर
- ग्राम स्तरीय दुग्ध संग्रह केन्द्र पर्यवेक्षक
- दूध परीक्षक
- ग्रीन हाउस गैसों का शमन
- दूध की गुणवत्ता आश्वासन
- मिल्क डिलीवरी बॉय
- दूध खरीद और इनपुट पर्यवेक्षक
- डेयरी उद्योग में अपशिष्ट प्रबंधन
- चारा और चारा प्रबंधन
- स्वच्छ दूध उत्पादन
- निर्णय समर्थन प्रणाली / डेटा विश्लेषिकी

सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस फॉर डेरी स्किल्स इन इंडिया